



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 2007/फाल्गुन 11, 1928

No. 218]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2007/PHALGUNA 11, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2007

का.आ. 308(अ).—केन्द्र सरकार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 1 जून, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 841(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में क्रम सं. 13 और महाराष्ट्र सरकार से संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“13.	महाराष्ट्र	मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय सभी मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश	बृहद बम्बई वाला क्षेत्र उनके संबंधित (न्यायिक) जिला क्षेत्र”
------	------------	--	---

[2007 की अधिसूचना सं. 1/फा. सं. 6/3/2005-ई.एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2007

S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), and in consultation with the Chief Justice of Bombay High Court, the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. S.O. 841(E), dated the 1st June, 2006, namely,—

In the Annexure to the said Notification, for serial number 13 and the entries pertaining to Maharashtra, the following shall be substituted, namely :—

“13.	Maharashtra	Principal Judge, City Civil and Sessions Court All the Principal District and Sessions Judges	Area comprising Greater Bombay. Area comprising their respective (Judicial) districts.”
------	-------------	--	--

[Notification No. 1 of 2007/F.No. 6/3/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2007

का.आ. 309(अ).—केन्द्र सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श से इस अधिसूचना के परिशिष्ट में यथा उल्लिखित सत्र न्यायालय/न्यायालयों को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियोजन के लिए उक्त अनुबंध में उक्त न्यायालयों के सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायालय/न्यायालयों के रूप में पदनामित करती है :—

परिशिष्ट

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित सत्र न्यायालय	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियोजन के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र
1.	पंजाब	सत्र न्यायाधीश, फरीदकोट	भटिंडा, फरीदकोट और मानसा के राजस्व जिले
		सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर	फिरोजपुर, मुक्तसर और मोगा के राजस्व जिले
		सत्र न्यायाधीश, जालंधर	गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और तरनतारन के राजस्व जिले
		सत्र न्यायाधीश, पटियाला	बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, संगरूर और एस.एस. नगर के राजस्व जिले
2.	हरियाणा	सत्र न्यायाधीश, अम्बाला	अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर के राजस्व जिले
		सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव	फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, नारनौल और रेवाड़ी के राजस्व जिले
		सत्र न्यायाधीश, हिसार	भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, जीन्द और सिरसा के राजस्व जिले
		सत्र न्यायाधीश, रोहतक	झज्जर, करनाल, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के राजस्व जिले
3.	चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	सत्र न्यायाधीश, चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ का राजस्व जिला

[2007 की अधिसूचना सं. 2/फा. सं. 6/3/2005-ई.एस.]

बी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2007

S.O. 309(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), and in consultation with the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, the Central Government designates the Court(s) of Sessions, as mentioned in the Annexure to this notification, as Special Court(s) for the area(s) specified in the said Annexure against the said Courts, for trial of offence punishable under Section 4 of the said Act :—

ANNEXURE

S.No.	State/Union Territory	Court of Sessions notified as Special Court under the Prevention of Money-laundering Act, 2002	Area specified for trial of offence punishable under Section 4 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002
1.	Punjab	Sessions Judge, Faridkot Sessions Judge, Ferozepur Sessions Judge, Jalandhar Sessions Judge, Patiala	Revenue Districts of Bhatinda, Faridkot and Mansa. Revenue Districts of Ferozepur, Muktsar and Moga. Revenue Districts of Gurdaspur, Amritsar, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Nawanshahr and Tarn Taran. Revenue Districts of Barnala, Fatehgarh Sahib, Ludhiana, Patiala, Rupnagar, Sangrur and S.A.S. Nagar.
2.	Haryana	Sessions Judge, Ambala Sessions Judge, Gurgaon Sessions Judge, Hisar Sessions Judge, Rohtak	Revenue Districts of Ambala, Kaithal, Kurukshetra, Panchkula and Yamunanagar Revenue Districts of Faridabad, Gurgaon, Mewat, Narnaul and Rewari Revenue Districts of Bhiwani, Fatehabad, Hisar, Jind and Sirsa Revenue Districts of Jhajjar, Karnal, Panipat, Rohtak and Sonapat.
3.	Union Territory, Chandigarh	Sessions Judge, Chandigarh	Revenue District Chandigarh.

[Notification No. 2 of 2007/F.No. 6/3/2005-E.S.]

V. P. ARORA, Under Secy.